vinetur

फ्रांस की शीर्ष अदालत में Cognac उत्पादन कटौती को अनाम समूह ने दी चुनौती

यह याचिका उस सरकारी आदेश को निशाना बनाती है, जिसमें 2025 की फसल सीमा घटाई गई थी, जबकि क्षेत्र घटती बिक्री और भारी स्टॉक्स से जूझ रहा है

शुक्रवार, 22 मई 2026



एक नया और रहस्यमय संघ Cognac उद्योग को फ्रांस की सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत तक ले गया है, और उसने उस सरकारी आदेश को चुनौती दी है जिसने 2025 की फसल के लिए उत्पादन सीमाएँ घटाईं तथा ऐसे क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया जो पहले से ही घटती बिक्री और भारी स्टॉक्स के दबाव में है.

Collectif 78.37 नामक इस समूह ने अप्रैल के अंत में Conseil d'État में अपना मामला दायर किया, फ्रांसीसी कृषि मंत्रालय और National Institute of Origin and Quality के अनुसार। यह संघ 7 अप्रैल को बनाया गया था और इसका नाम एथेनॉल के क्वथनांक, 78.37 डिग्री सेल्सियस, से लिया गया है। इसका घोषित उद्देश्य Cognac क्षेत्र के

viticulturists, distillers और producers के हितों की रक्षा करना है। लेकिन इसके सदस्यों के नाम सार्वजनिक नहीं हैं, और इसके उपनियम भी उन्हें इसी तरह गोपनीय रखने के लिए तैयार किए गए हैं.

दायर दस्तावेज़ में केवल अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की पहचान दी गई है ; दोनों का संबंध पेरिस की कानून फर्म DDCT से है, जो संघ का पंजीकृत कार्यालय भी है। फर्म ने पेशेवर गोपनीयता का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। इस गुमनामी ने Charente के अंगूर-बागानों में इस बात को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं कि चुनौती के पीछे कौन है और उन्होंने क्षेत्र के भीतर खुलकर सामने आने के बजाय पेरिस के वकीलों के जरिये कार्रवाई क्यों चुनी.

विवाद का केंद्र 20 फ़रवरी 2026 का एक अंतर-मंत्रालयी आदेश है, जिसमें 2025 की फसल के लिए Cognac की उपज 7.65 hectoliters of pure alcohol per hectare तय की गई थी। यह कदम बिक्री में तेज़ सुस्ती और बढ़ते भंडार के बाद उत्पादन पर अंकुश लगाने की व्यापक कोशिश का हिस्सा था। अप्रैल 2026 तक के 12 महीनों में Cognac की शिपमेंट 13% घटकर 139.8 million bottles रह गई, जबकि Asia को निर्यात 7% और North America को 26% कम हुआ.

उपज में कटौती ने उद्योग के अलग-अलग हिस्सों को अलग-अलग कारणों से नाराज़ किया है। उत्पादकों का कहना है कि वे अधिक उत्पादन करना चाहते हैं ताकि निश्चित लागतों को बड़े वॉल्यूम पर बाँटा जा सके। व्यापारियों का कहना है कि उनके पास पहले से ही बहुत अधिक स्टॉक है और बाज़ार में और शराब आने की ज़रूरत नहीं है। नतीजा यह है कि सेक्टर में असंतोष का एक दुर्लभ मेल बन गया है, भले ही उसके कारण एक-दूसरे के उलट हों.

Bureau National Interprofessionnel de Cognac के अध्यक्ष Florent Morillon ने कहा कि यह अनाम याचिका खेदजनक है और इससे संकेत मिलता है कि यह appellation की सामूहिक रक्षा नहीं, बल्कि निजी आर्थिक हितों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि कठिन बाज़ार का सामना कर रहे इस उद्योग को एकजुटता की ज़रूरत है.

स्थानीय अधिकारियों और उद्योग से जुड़े लोगों ने सावधानी बरती है, लेकिन संदेह भी जताया है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मामले के पीछे क्षेत्र के उत्पादक या अन्य प्रभावशाली पक्ष हो सकते हैं, जो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते क्योंकि उनका रुख अलोकप्रिय है। कुछ अन्य इसे ऐसे सेक्टर के भीतर पुरानी दरारें फिर से खोलने की कोशिश मानते हैं, जो पहले से ही growers, merchants और interprofessional bodies में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी कर रहा है.

अंगूर-बागान क्षेत्र से जुड़े एक निर्वाचित प्रतिनिधि ने कहा कि यह जानना असंभव है कि संघ के पीछे कितने लोग हैं या आदेश को रद्द कराने से आगे अदालत से वे ठीक-ठीक क्या माँगेंगे। मामले से जुड़े एक अन्य स्रोत ने कहा कि Conseil d'État में कोई भी कानूनी चुनौती महंगी होगी और substantive stage तक पहुँचने में महीनों लग सकते हैं.

मंत्रालय ने कहा कि Collectif 78.37 ने न केवल आदेश को निरस्त करने की माँग की, बल्कि French administrative law के तहत €3,000 कानूनी खर्च भी माँगा। संघ के उपनियमों में कहा गया है कि उसका उद्देश्य उत्पादन और विपणन को नियंत्रित करने वाले कानूनी, आर्थिक, agronomic और पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, साथ ही अपने सदस्यों के भौतिक और पेशेवर हितों की रक्षा करना तथा किसी भी ऐसे प्रशासनिक या नियामकीय निर्णय का विरोध करना है जो उन्हें नुकसान पहुँचा सकता हो.

फिलहाल Cognac में कोई भी निश्चित नहीं कह पा रहा कि यह मामला उत्पादन नियमों में बदलाव लाएगा या पहले से दबाव झेल रहे बाज़ार में अनिश्चितता की एक और परत जोड़ देगा.